



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30112024-259052  
CG-DL-E-30112024-259052

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 956]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 29, 2024/अग्रहायण 8, 1946

No. 956]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 29, 2024/AGRAHAYANA 8, 1946

पंजाब नैशनल बैंक

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2024

फा. सं. HRDD/POL/OSR(E).—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 12 की उपधारा (2) के साथ पठित, धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब नैशनल बैंक का निदेशक मंडल, भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श के पश्चात् तथा केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग के पत्र संख्या 4/2/2/2015-आईआर, दिनांक 18 दिसंबर, 2020 के अनुसरण में की गई या किए गए कार्यों को छोड़कर, 1 नवंबर, 2017 से तथा आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि तक, एतद्वारा पंजाब नैशनल बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 को संशोधित करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा:-

- (1) इन विनियमों को पंजाब नैशनल बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2024 कहा जाएगा।
- (2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे।

2. पंजाब नैशनल बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 (जिसे इसके पश्चात् उक्त विनियम कहा जाएगा) के विनियम 3 में, —

(i) खंड (च) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“(च) चिकित्सा सुविधाओं के प्रयोजनों के लिए तथा छुट्टी किराया रियायत के प्रयोजन के लिए 'परिवार' का अर्थ होगा, अधिकारी का जीवनसाथी, पूर्णतः आश्रित अविवाहित बच्चे (सौतेले बच्चों तथा विधिक रूप से गोद लिए गए बच्चों सहित), चालीस प्रतिशत या अधिक दिव्यांगता वाले पूर्णतः आश्रित शारीरिक तथा मानसिक रूप से दिव्यांग भाई या बहन, विधवा पुत्रियां तथा आश्रित तलाकशुदा या परित्यक्त पुत्रियां, अविवाहित या तलाकशुदा या पति से अलग हुई या विधवा बहनें तथा अधिकारी पर पूर्णतः आश्रित माता-पिता।

**स्पष्टीकरण. -**

(क) "पूर्ण रूप से आश्रित परिवार के सदस्य" का अर्थ परिवार के ऐसे सदस्य से होगा जिसकी आय ₹12,000/- प्रति माह से अधिक नहीं है। यदि माता-पिता में से किसी एक की आय ₹12,000/- प्रति माह से अधिक है अथवा माता-पिता दोनों की कुल आय ₹12,000/- प्रति माह से अधिक है, तो माता-पिता दोनों को अधिकारी पर पूर्णतः आश्रित नहीं माना जाएगा।

(ख) एक विवाहित महिला अधिकारी अपने प्राकृतिक माता-पिता या सास-ससुर को परिवार की परिभाषा में शामिल कर सकती है, परंतु दोनों को नहीं, बशर्ते कि माता-पिता अथवा सास-ससुर पूर्णतः उस पर निर्भर हों।

**नोट 1 :** चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति योजना के उद्देश्य से, सभी अधिकारियों अर्थात् पुरुष अथवा महिला हेतु, आश्रित माता-पिता अथवा सास-ससुर में से किसी दो को कवर किया जाएगा। अधिकारी के पास आश्रितों में से किसी एक अथवा दोनों को प्रतिस्थापित करने का विकल्प होगा।

**नोट 2:** किसी अधिकारी के शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को आयु या वैवाहिक स्थिति पर ध्यान दिए बिना, आय मानदंड के अधीन, आश्रितों के रूप में परिभाषित किया जाएगा ;”

(ii) खंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(i) 'प्रबंध निदेशक' से अर्थ बैंक का प्रबंध निदेशक तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी से है;”

3. उक्त विनियमों के विनियम 4 में, -

(i) उप-विनियम (6) में, स्पष्टीकरण का लोप किया जाएगा;

(ii) उप-विनियम (7), (8) तथा (9) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

“(7) 1 नवंबर, 2017 से प्रत्येक ग्रेड के समक्ष विनिर्दिष्ट वेतनमान निम्नानुसार होंगे:—

(क) शीर्ष कार्यपालक ग्रेड

वेतनमान VII = ₹ 116120 – 3220/4 – 129000

वेतनमान VI = ₹ 104240 - 2970/4 - 116120

(ख) वरिष्ठ प्रबंधन ग्रेड

वेतनमान V = ₹ 89890 – 2500/2 – 94890 – 2730/2 - 100350

वेतनमान IV = ₹ 76010 – 2220/4 – 84890– 2500/2 – 89890

## (ग) मध्यम प्रबंधन ग्रेड

वेतनमान III = ₹ 63840 -1990/5- 73790 - 2220/2 - 78230

वेतनमान II = ₹ 48170-1740/1 - 49910 -1990/10 - 69810

## (घ) कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड

वेतनमान I = ₹ 36000 -1490/7- 46430-1740/2-49910-1990/7-63840

**स्पष्टीकरण.-** प्रत्येक अधिकारी जो 31 अक्टूबर, 2017 को लागू वेतनमान द्वारा शासित है, को 1 नवंबर, 2017 को स्तर दर स्तर आधार पर इस उप-विनियम में निर्धारित वेतनमान में फिट किया जाएगा अर्थात्, संबंधित वेतनमान में पहले चरण से आगे के अनुरूप चरणों में तथा वेतन वृद्धि सदैव की भांति प्रतिवार्षिक की तिथि को होगी, सिवाय जहां अन्यथा प्रावधान किया गया हो।

## (8) 31 मार्च, 2020 से, शीर्ष कार्यपालक ग्रेड वेतनमान-VIII के लिए निर्दिष्ट वेतनमान निम्नानुसार होंगे:—

वेतनमान- VIII = रु.166350-4400/4 – 183950

## (9) उप-विनियम (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) और (8) में किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि बैंक को हर समय इन सभी ग्रेडों में सेवारत अधिकारी रखने की आवश्यकता है।

## (10)(क) 1 नवम्बर, 2012 से अधिकारियों को निम्नानुसार विशेष भत्ते दिए जाएंगे:—

वेतनमान I – III - मूल वेतन का 7.75% एवं लागू महंगाई भत्ता;

वेतनमान IV – V - मूल वेतन का 10% एवं लागू महंगाई भत्ता;

वेतनमान VI – VII - मूल वेतन का 11% एवं लागू महंगाई भत्ता।

## (ख) 1 नवंबर, 2017 से अधिकारियों को निम्नानुसार विशेष भत्ते का भुगतान किया जाएगा:—

वेतनमान I – III - मूल वेतन का 16.40 % एवं लागू महंगाई भत्ता;

वेतनमान IV – V - मूल वेतन का 19% एवं लागू महंगाई भत्ता;

वेतनमान VI - VIII - मूल वेतन का 20% एवं लागू महंगाई भत्ता;

बशर्ते कि वेतनमान VIII के अधिकारी 31 मार्च, 2020 से विशेष भत्ते हेतु पात्र हो।

**टिप्पणी:** उप-विनियम 10 के खंड (क) तथा (ख) में निर्दिष्ट विशेष भत्ते तथा उस पर लागू महंगाई भत्ते की गणना सेवानिवृत्ति लाभों यथा पेंशन सहित नई पेंशन योजना, भविष्य निधि तथा ग्रेच्युटी हेतु नहीं की जाएगी।"

## 4. उक्त विनियमों के विनियम 5 में, -

## (i) उप-विनियम (1) हेतु, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(1) विनियम 4 के उप-विनियम (7) तथा (8) के प्रावधानों के अधीन, 1 नवंबर, 2017 से वेतन वृद्धि निम्नलिखित के अधीन प्रदान की जाएगी, अर्थात्: -

(क) विनियम 4 के उप-विनियम (7) तथा (8) में निर्धारित वेतनमान में निर्दिष्ट वेतन वृद्धि, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के अधीन, वार्षिक आधार पर अर्जित होगी तथा जिस माह में यह देय हो, उसके प्रथम दिन प्रदान की जाएगी ;

(ख) अपने संबंधित वेतनमान में चरम पर पहुंचने के एक वर्ष पश्चात्, वेतनमान I तथा वेतनमान II के अधिकारियों को अगले उच्चतर वेतनमान में स्थिरता वेतन वृद्धि सहित आगे की वेतन वृद्धि नीचे खंड (सी) में निर्दिष्ट दक्षता बार के अधीन प्रदान की जाएगी।

(ग) कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड वेतनमान I के अधिकारी, जो उच्चतर वेतनमान की अधिकता पर पहुंचने के पश्चात् खंड (ख) के अनुसार मध्यम प्रबंधन ग्रेड वेतनमान II के वेतनमान में प्रवेश कर गए हैं, को सेवा के प्रत्येक दो पूर्ण वर्षों के लिए पांच स्थिर वेतन वृद्धि के लिए पात्र होंगे, जिनमें से प्रथम दो वेतन वृद्धियां प्रत्येक रु.1990/- की होंगी तथा अगली तीन वेतन वृद्धियां प्रत्येक रुपये 2220/- की होंगी:

बशर्ते कि अधिकारी चौथी वेतनवृद्धि जारी होने के दो वर्ष पश्चात् अथवा 1 नवम्बर, 2017 को, जो भी बाद में हो, पांचवीं वेतनवृद्धि हेतु पात्र होगा।

(क) मध्यम प्रबंधन ग्रेड वेतनमान II के अधिकारी, जो खंड (ख) के अनुसार उच्चतर वेतनमान की अधिकता पर पहुंचने के पश्चात् मध्यम प्रबंधन ग्रेड वेतनमान III के वेतनमान में प्रवेश कर गए हैं, सेवा के प्रत्येक दो पूर्ण वर्षों के लिए रुपये 2220/- की पांच स्थिर वेतन वृद्धि के लिए पात्र होंगे:

बशर्ते कि अधिकारी चौथी वेतनवृद्धि जारी होने के दो वर्ष पश्चात् अथवा 1 नवम्बर, 2017 को, जो भी बाद में हो, पांचवीं वेतनवृद्धि के लिए पात्र होगा।

(ख) विशेष्य मध्यम प्रबंधन ग्रेड वेतनमान III में अधिकारी अर्थात्, जो मध्यम प्रबंधन ग्रेड वेतनमान III में भर्ती किए गए हैं या पदोन्नत किए गए हैं, वे छठे स्थिर वेतन वृद्धि के लिए पात्र होंगे, जिनमें से रु.2220/- की प्रथम चार स्थिर वेतन वृद्धि अधिकता पर पहुंचने के पश्चात् प्रत्येक दो वर्ष की पूर्ण की गई सेवा के पश्चात् दी जाएगी तथा चौथी स्थिर वेतन वृद्धि प्राप्त करने के पश्चात् रु. 2500/- की अगली दो स्थिर वेतन वृद्धि प्रत्येक दो वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात् दी जाएगी।

बशर्ते कि छठी वेतनवृद्धि पांचवीं वेतनवृद्धि के जारी होने के दो वर्ष पश्चात् या 1 नवंबर, 2017 जो भी बाद में हो, को जारी की जाएगी।

(ग) वरिष्ठ प्रबंधन ग्रेड वेतनमान IV के अधिकारी, वेतनमान की अधिकता पर पहुंचने के पश्चात्, सेवा के प्रत्येक दो पूर्ण वर्षों के लिए दो स्थिर वेतन वृद्धि के लिए पात्र होंगे, जिनमें से प्रथम स्थिर वेतन वृद्धि रु. 2500/- रुपये की होगी तथा द्वितीय स्थिर वेतन वृद्धि रु. 2730/- रुपये की होगी:

बशर्ते कि अधिकारी प्रथम स्थिर वेतन वृद्धि जारी होने के दो वर्ष पश्चात् अथवा 1 नवम्बर, 2017 को, जो भी बाद में हो, द्वितीय स्थिर वेतन वृद्धि के लिए पात्र होंगे;

(घ) 1 नवंबर, 2017 तक बैंकों में अपनी सेवा के दौरान स्केल I से स्केल IV तक के अधिकारियों द्वारा प्राप्त स्थिर वेतन वृद्धि को यहां पूर्व दी गई आवधिकता के अनुसार उनके अधिकतम वेतन तक पहुंचने की तिथि से तीन वर्ष की आवधिकता से दो वर्ष की आवधिकता में पुनः समायोजित किया जाएगा तथा अधिकारी संशोधित आवधिकता के अनुसार 1 नवंबर, 2017 से स्थिर वेतन वृद्धि के लिए मान्य रूप से पात्र होंगे जो सेवानिवृत्ति लाभ के लिए पात्र होंगे। हालांकि, स्थिर वेतन वृद्धि की ऐसी संशोधित तथा पुनः समायोजित आवधिकता के कारण मौद्रिक लाभ 1 नवंबर, 2020 या पात्रता की वास्तविक तिथि, जो भी बाद में हो, से देय होगा ;

(ङ) वरिष्ठ प्रबंधन ग्रेड वेतनमान V के अधिकारी वेतनमान अधिकता तक पहुंचने के दो वर्ष पश्चात् या 1 नवंबर, 2020 को, जो भी बाद में हो, रु. 2970 की एक स्थिर वेतन वृद्धि के लिए पात्र होंगे।

बशर्ते कि ऐसी वेतनवृद्धि उस अधिकारी को नहीं दी जाएगी जो पदोन्नति का प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है।

**स्पष्टीकरण.-** इस उप-विनियम के अंतर्गत अगले उच्चतर वेतनमान में ऐसी वेतनवृद्धि प्रदान करना पदोन्नति नहीं माना जाएगा तथा अधिकारियों के विशेषाधिकार, सुविधाएं, कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व उनके मूल पद के अनुसार जारी रहेंगी। "

(ii) उप-विनियम (2) में, स्पष्टीकरण में, खंड (छ) के पश्चात् तथा टिप्पणी से पूर्व, निम्नलिखित खंड सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(झ) 1 नवंबर, 2017 को या से, अन्य बातें समान होने पर, व्यावसायिक योग्यता वेतन की मात्रा नीचे दी गई तालिका में निर्दिष्ट के अनुसार संशोधित होगी: -:-

**तालिका**

वे कार्मिक जिन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के जूनियर एसोसिएट या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के सर्टिफाइड एसोसिएट पार्ट I की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।	(i) तनमान की अधिकता पर पहुंचने के एक वर्ष पश्चात् प्रति माह रु. 1020/- ।
वे कार्मिक जिन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के सर्टिफाइड एसोसिएट के दोनों भाग उत्तीर्ण कर लिए हों ।	(ii) वेतनमान की उच्चतम सीमा पर पहुंचने के एक वर्ष पश्चात् रु.1020 प्रति माह ।  (iii) वेतनमान के उच्चतम सीमा पर पहुंचने के दो वर्ष पश्चात् रु. 2550 प्रति माह:

बशर्ते वेतनमान के अधिकतम स्तर पर/सीमा पर पहुंचने के पश्चात् इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के जूनियर एसोसिएट या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के सर्टिफाइड एसोसिएट (दोनों में से कोई एक या दोनों भाग) योग्यता प्राप्त करने वाले अधिकारी कार्मिक को ऐसी योग्यता प्राप्त करने की तिथि से व्यावसायिक योग्यता वेतन की प्रथम किस्त प्रदान की जाएगी तथा व्यावसायिक योग्यता वेतन की बाद की किस्तों को व्यावसायिक योग्यता वेतन की पहली किस्त की तिथि के संदर्भ जारी किया जाएगा।"

(iii) उप-विनियम (3) में, -

(क) खंड (च) में, तालिका के पश्चात् टिप्पणी ( i ) से (vi) का लोप किया जाएगा;

(ख) खंड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

“(ज) 1 नवंबर, 2017 से, अन्य बातें समान होने पर, मकान किराया भत्ते के साथ निर्धारित व्यक्तिगत वेतन निम्नलिखित दरों पर होगा तथा सेवा की पूरी अवधि के लिए समान रहेगा:

## तालिका

क्रम सं.	वेतन वृद्धि घटक (रु.)	1 नवंबर, 2017 को वेतन वृद्धि घटकों पर महंगाई भत्ता (रु.)	कुल निश्चित वैयक्तिक देय वेतन जहां बैंक की आवासीय सुविधा प्रदान की जाती है (रु.)
1	(1)	(2)	(3)
2	1990	53	2043
3	2220	59	2279
4	2500	66	2566
5	2730	73	2803
6	2970	79	3049
7	3220	86	3306

## टिप्पणी:

- (i) इस उप-विनियम के खंड (ख), (ग), (घ), (ङ), (च) तथा (छ) में तालिका के कॉलम (3) के अंतर्गत यथानिर्दिष्ट, निश्चित वैयक्तिक भत्ता या निश्चित वैयक्तिक वेतन उन अधिकारी कार्मिकों को देय होगा, जिन्हें बैंक का आवास उपलब्ध कराया गया है।
- (ii) मकान किराया भत्ते के लिए पात्र अधिकारियों के लिए निश्चित वैयक्तिक भत्ता या निश्चित वैयक्तिक वेतन, उपर्युक्त तालिका के कॉलम (1) तथा (2) के अंतर्गत निर्दिष्ट कुल राशि होगी तथा संबंधित अधिकारी कार्मिकों द्वारा विनियम 4 के उप-विनियम (2), (3), (4), (5) (6) तथा (7) में यथानिर्दिष्ट वेतनमान की अंतिम वेतन वृद्धि अर्जित करने पर प्राप्त मकान किराया भत्ता होगा;
- (iii) केवल वे अधिकारी जो 1 नवम्बर, 1993 को या उससे पूर्व बैंक में सेवारत हों, वे अपने नियोजित वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुंचने के एक वर्ष पश्चात् निश्चित वैयक्तिक वेतन के लिए पात्र होंगे।
- (iv) 1 नवम्बर, 1999 को एवं से, निश्चित वैयक्तिक वेतन जारी किए जाने के कारण उप-विनियम (2) के स्पष्टीकरण (ग) के अनुसार व्यावसायिक अर्हता वेतन जारी किए जाने की अनुसूची में कोई परिवर्तन नहीं होगा।  

बशर्ते जहां व्यावसायिक अर्हता वेतन की कोई किस्त, जो पूर्ववर्ती उपबंधों के कारण एक वर्ष के लिए आगे बढ़ गई है तथा 1 नवम्बर, 1999 को या उसके पश्चात जारी होने वाली है वह अधिकारी को इसी तिथि से जारी की जाएगी तथा व्यावसायिक अर्हता वेतन की दूसरी किस्त, यदि कोई हो, 1 नवम्बर, 2000 को जारी की जाएगी।
- (v) निश्चित व्यक्तिगत भत्ता या निश्चित व्यक्तिगत वेतन का वेतन वृद्धि घटक सेवानिवृत्ति लाभ के लिए रैंक किया जाएगा।
- (vi) कोई अधिकारी, जिसने उपर्युक्त खंड (क) के अनुसार अग्रिम वेतन वृद्धि अर्जित की है, वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुंचने के एक वर्ष पश्चात्, उपर्युक्त खंड (ख), (ग), (घ), (ङ) तथा (च) में यथाउल्लिखित निश्चित वैयक्तिक भत्ता या निश्चित वैयक्तिक वेतन की मात्रा प्राप्त करेगा।
- (त) 31 मार्च, 2020 को एवं से, अन्य बातें समान होने पर, शीर्ष कार्यपालक संवर्ग स्केल-VIII में मुख्य महाप्रबंधक के पद के लिए मकान किराया भत्ते के साथ निश्चित वैयक्तिक वेतन नीचे दी गई तालिका में दी गई दरों के अनुसार होगा तथा संपूर्ण सेवा अवधि के लिए स्थिर रहेगा:

## तालिका

वेतन वृद्धि घटक (रु.)	वेतन वृद्धि घटकों पर महंगाई भत्ता (रु.)	कुल निश्चित वैयक्तिक वेतन देय जहां बैंक की सुविधा प्रदान की जाती है (रु.)
(1)	(2)	(3)
4400	117	4517"

5. उक्त विनियमों के विनियम 20 में, उप-विनियम (1) में, खंड (ग) में, शब्द "चेयरमैन तथा" का लोप कर दिया जाएगा।

6. उक्त विनियमों के विनियम 21 में,—

(क) उप-विनियम (6) में, स्पष्टीकरण में खंड (ख) के, कोष्ठक, शब्द तथा अक्षर "(च) तथा (छ)" के स्थान पर, कोष्ठक, शब्द तथा अक्षर "(च), (छ) तथा (ज)" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(ख) उप-विनियम (6) के पश्चात् निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(7) 1 नवम्बर, 2017 को, से अखिल भारतीय औसत श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) आधार 1960=100 के तिमाही औसत में 6352 अंकों से अधिक प्रत्येक चार अंकों की वृद्धि या गिरावट के लिए वेतन के 0.07% की दर से महंगाई भत्ता देय होगा।"

7. उक्त विनियमों के विनियम 22 में, उप-विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्: -

1 नवम्बर, 2017 को एवं से,—

(क) जहां किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा प्रदान की जाती है, वहां पदस्थ वेतनमान के प्रथम चरण में मूल वेतन के 0.50 प्रतिशत के बराबर राशि या आवास के लिए मानक किराया, जो भी कम हो, उससे वसूली की जाएगी;

(ख) जहां किसी अधिकारी को बैंक द्वारा कोई आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती है, अधिकारी निम्नलिखित तालिका में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार मकान किराया भत्ते के लिए पात्र होगा, अर्थात्:

## तालिका

क्रम सं.	तैनाती स्थल	मकान किराया भत्ता
1.	(2)	(3)
2.	ग्रुप ए में प्रमुख "ए" श्रेणी के शहर तथा परियोजना क्षेत्र केंद्र	वेतन का 9.0%
3.	क्षेत्र I के अन्य स्थान तथा ग्रुप बी परियोजना क्षेत्र केंद्र तथा गोवा राज्य	वेतन का 8.0%
4.	अन्य स्थान	वेतन का 7.0%:

बशर्ते कि यदि कोई अधिकारी किराये की रसीद प्रस्तुत करता है तो उसे देय मकान किराया भत्ता उसके द्वारा आवासीय निवास के लिए भुगतान किया गया वास्तविक किराया होगा जो उपर्युक्त तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित दरों के अनुसार देय मकान किराया भत्ते के अधिकतम 150 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के साथ उसके पदस्थ वेतनमान के प्रथम स्तर में देय 0.50 प्रतिशत से अतिरिक्त होगा।

**टिप्पणी:-** अधिकारियों के उनके स्वामित्व वाले आवास की लागत से जुड़े मकान किराया भत्ते के दावे को भी पूर्ववत मकान किराया भत्ते के 150 प्रतिशत तक सीमित रखा जाएगा।

8. उक्त विनियमों के विनियम 23 में,

(क) उप- विनियम (1), (2), (3), (4) तथा (5) के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्: -

“(1) 1 नवम्बर, 2017 को एवं से, यदि कोई अधिकारी निम्नलिखित तालिका के कॉलम (1) में उल्लिखित स्थान पर सेवा कर रहा है, तो कॉलम (2) में उल्लिखित दर पर उस स्थान के प्रति नगर प्रतिपूरक भत्ता देय होगा:—

**तालिका**

क्रम सं.	स्थान	दर
(1)	(2)	(3)
1.	क्षेत्र 1 तथा उससे ऊपर तथा गोवा राज्य में स्थित स्थान	रु. 1400/- प्रति माह
2.	पांच लाख तथा उससे अधिक जनसंख्या वाले स्थान तथा राज्यों की राजधानियाँ तथा चंडीगढ़, पुडुचेरी तथा पोर्ट ब्लेयर	रु. 1150/- प्रति माह

- (2) 1 नवम्बर, 2017 को एवं से विशेष क्षेत्र भत्ते की दरें इन विनियमों की अनुसूची में यथानिर्दिष्ट के अनुसार होंगी।
- (3) 1 नवम्बर, 2017 को या से, यदि कोई अधिकारी समूह ए या समूह बी में आने वाले परियोजना क्षेत्र के रूप में निर्दिष्ट क्षेत्र में सेवारत है, तो वह समूह 'ए' या समूह 'बी' के रूप में क्षेत्र के वर्गीकरण के अनुसार क्रमशः रु.600 प्रति माह या रु.525 प्रति माह की दर से परियोजना क्षेत्र प्रतिपूरक भत्ते के लिए पात्र होगा।
- (4) 1 नवम्बर, 2020 को या से, यदि किसी अधिकारी को शैक्षणिक वर्ष के मध्य में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है तथा यदि उसके एक या एक से अधिक बच्चे पूर्व स्थान पर स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो वह सभी बच्चों के संबंध में, बाद वाले स्थान पर रिपोर्ट करने की तिथि से शैक्षणिक वर्ष के अंत तक रु. 1650/- प्रति माह के मध्य शैक्षणिक वर्ष स्थानांतरण भत्ते के लिए पात्र होगा, बशर्ते कि यदि सभी बच्चे पूर्व स्थान पर पढ़ना बंद कर देते हैं तो ऐसा भत्ता बंद हो जाएगा।
- (5) 1 नवम्बर, 2020 से, यदि किसी अधिकारी को बैंक के बाहर सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है, तो वह उस पद से जुड़ी परिलब्धियां प्राप्त करने का विकल्प चुन सकता है, जिस पर उसे प्रतिनियुक्त किया गया है, या वह अपने वेतन के अतिरिक्त, वेतन के 7.75 प्रतिशत की दर से प्रतिनियुक्ति भत्ता, जो अधिकतम रु. 6000/- प्रति माह तक होगा, प्राप्त कर सकता है तथा ऐसे अन्य भत्ते, जो उसे उस स्थान पर बैंक की सेवा में तैनात होने पर मिलते, प्राप्त हो सकते हैं:

बशर्ते कि यदि उसे ऐसे संगठन में प्रतिनियुक्त किया जाता है जो उसी स्थान पर स्थित है जहां वह प्रतिनियुक्ति से ठीक पहले तैनात था, उसे अपने वेतन के 4 प्रतिशत के बराबर प्रतिनियुक्ति भत्ता मिलेगा जो अधिकतम रु.3000 प्रति माह तक हो सकता है:



बशर्ते कि बैंक के प्रशिक्षण प्रतिष्ठान में संकाय सदस्य के रूप में प्रतिनियुक्ति पर आने वाला अधिकारी अपने वेतन के 4 प्रतिशत की दर से प्रतिनियुक्ति भत्ते के लिए पात्र होगा, जो अधिकतम रु. 3000 प्रति माह के अधीन होगा।"

(ख) उप-विनियम (8) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(8) 1 नवंबर, 2017 को एवं से, यदि किसी दिन के दौरान कार्य घंटों को न्यूनतम दो घंटे के अंतराल के साथ विभाजित किया जाता है, तो अधिकारी 300 रुपये प्रति माह की दर से विभाजित ड्यूटी भत्ते के लिए पात्र होगा।"

(ग) उप-विनियम (10) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

(10) 1 नवंबर, 2017 को एवं से, कोई भी अधिकारी नीचे दी गई तालिका में निर्दिष्ट पहाड़ी तथा ईंधन भत्ते के लिए पात्र होगा, अर्थात्: -

तालिका

क्रम सं.	स्थान	दर
(1)	(2)	(3)
1.	1000 मीटर या उससे अधिक लेकिन 1500 मीटर से कम ऊंचाई वाला स्थान तथा मर्करा टाउन	वेतन का 2%, अधिकतम रु.1125/- प्रति माह तक
2.	1500 मीटर या उससे अधिक किन्तु 3000 मीटर से कम ऊंचाई वाला स्थान	वेतन का 2.5%, अधिकतम रु.1500/- प्रति माह तक
3.	3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाला स्थान	वेतन का 5%, अधिकतम 3000/- रुपये प्रति माह तक";

(घ) उप-विनियम (11) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:

"(11) 1 नवंबर, 2017 को या से कोई भी अधिकारी रु. 600/- प्रतिमाह के शिक्षण भत्ते के साथ उस पर महंगाई भत्ते के लिए पात्र होगा।

(ङ) उप-विनियम (11) के पश्चात् निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"(12) 1 नवंबर 2017 को या से, ऐसे अधिकारी जो नगर प्रतिपूरक भत्ते के लिए पात्र क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों में तैनात हैं, रु.700/- प्रतिमाह के निश्चित भत्ते के लिए पात्र होंगे। इस निश्चित भत्ते की गणना महंगाई भत्ते, सेवानिवृत्ति लाभ अर्थात् पेंशन सहित नई पेंशन योजना, भविष्य निधि तथा ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए नहीं की जाएगी।"

"(13) वित्तीय वर्ष 2020-21 से, सभी अधिकारियों को देय सामान्य वेतन के अतिरिक्त परिचालन लाभ या शुद्ध लाभ के आधार पर वार्षिक रूप से कार्यनिष्पादन आधारित प्रोत्साहन देय होगा। नीचे उल्लिखित प्रदर्शन पर आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) मैट्रिक्स द्वारा बैंक के वार्षिक कार्यनिष्पादन के आधार पर देय राशि (वेतन के दिनों की संख्या = मूल + महंगाई भत्ता) तय होगी :

क्रम सं.	परिचालन लाभ में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि	दिनों की संख्या जिसके लिए वेतन (मूल + महंगाई भत्ता) का भुगतान किया जाएगा
(1)	(2)	(3)
1.	< 5%	शून्य
2.	5% से 10%	5 दिन

3.	> 10% से 15%	10 दिन*
4.	> 15%	15 दिन*
*तीसरा तथा चौथा स्लैब तभी देय होगा जब बैंक का शुद्ध लाभ हो। यदि बैंक के परिचालन लाभ में 5 प्रतिशत या उससे अधिक की वृद्धि हुई है, लेकिन शुद्ध लाभ नहीं हुआ है, तो न्यूनतम 5 दिन का दूसरा स्लैब देय होगा।		

9. उक्त विनियमों के विनियम 24 में, उप-विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“(1) 1 नवंबर, 2017 को एवं से, कोई भी अधिकारी स्वयं तथा परिवार के लिए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होगा, बशर्ते कि अधिकारी ने स्वयं ऐसा व्यय किया हो तथा दावा की गई राशियों के लिए लेखा विवरण भी हो, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में निर्दिष्ट है, अर्थात्:--

तालिका

क्रम सं.	श्रेणी	प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा
(1)	(2)	(3)
1.	कनिष्ठ प्रबंधन तथा मध्यम प्रबंधन ग्रेड	रु.10300/- प्रति वर्ष या व्यय की गई राशि जो भी कम हो
2.	वरिष्ठ प्रबंधन तथा शीर्ष कार्यपालक ग्रेड	रु.12300/- प्रति वर्ष या व्यय की गई राशि जो भी कम हो

टिप्पणी:- (i) किसी अधिकारी को अप्रयुक्त चिकित्सा सहायता को संचित करने की अनुमति दी जा सकेगी, ताकि किसी भी समय यह राशि उपर्युक्त अधिकतम राशि से तीन गुना अधिक न हो;

या

(ii) वर्ष 2017 के लिए, चिकित्सा सहायता योजना के अंतर्गत चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति दो माह अर्थात् नवम्बर, 2017 तथा दिसम्बर, 2017 के लिए आनुपातिक रूप से बढ़ाई जाएगी।”

10. उक्त विनियम के विनियम 25 में, उप-विनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“(2) उप-विनियम (1) में निहित किसी बात के होते हुए भी, बैंक किसी अधिकारी को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए स्वतंत्र होगा, जिसके लिए अधिकारी द्वारा 1 नवंबर, 2017 को एवं से, पदस्थ वेतनमान के प्रथम चरण में मूल वेतन के 0.50 प्रतिशत के बराबर राशि या आवास के लिए मानक किराया, जो भी कम हो, का भुगतान किया जाएगा:

बशर्ते कि जहां अधिकारी को ऐसे आवास पर फर्नीचर उपलब्ध कराया गया हो, वहां वेतनमान के प्रथम चरण में मूल वेतन के 0.10 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त राशि बैंक द्वारा उससे वसूल की जाएगी;

बशर्ते कि जहां बैंक द्वारा ऐसी आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, वहां बिजली, पानी, गैस तथा सफाई के लिए व्यय अधिकारी द्वारा वहन किया जाएगा।"

11. उक्त विनियमों के विनियम 32 में, उप-विनियम (2) में, उपबंध के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

**"स्पष्टीकरण.—** इस विनियम के प्रयोजन के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि—

- (क) वर्ष 2017 या इसके बाद के वर्षों में नहीं लिए गए आकस्मिक अवकाश अगले पांच वर्षों में समाप्त हो जाएगी;
- (ख) 1 नवंबर 2020 को एवं से, अधिकारी द्वारा अप्रयुक्त आकस्मिक अवकाश को चिकित्सा के आधार पर अनुमत किया जाएगा तथा चार दिनों के अप्रयुक्त आकस्मिक अवकाश की अवधि के लिए कोई चिकित्सा प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।"

12. उक्त विनियमों के विनियम 33 में,—

- (क) उप-विनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(4) 1 जून, 2015 को एवं से, विशेषाधिकार अवकाश अधिकतम दो सौ सत्तर दिन तक संचित किया जा सकेगा, केवल उन मामलों को छोड़कर जहां अवकाश के लिए आवेदन किया गया हो तथा उसे अस्वीकार कर दिया गया हो:

बशर्ते कि विशेषाधिकार अवकाश का नकदीकरण अधिकतम दो सौ चालीस दिनों तक सीमित होगा।

इसके अतिरिक्त यह भी प्रावधान है कि कैलेंडर वर्ष, 2020 से, कोई अधिकारी अपनी पसंद के किसी भी त्यौहार के समय प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के लिए पांच दिनों की दर से विशेषाधिकार अवकाश के नकदीकरण के लिए भी पात्र होगा तथा कोई अधिकारी जो 1 जनवरी, 2020 को पचपन वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो तथा उससे अधिक आयु का हो, वह एक बारगी उपाय के रूप में अपनी सेवानिवृत्ति तक प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के लिए सात दिनों की दर से विशेषाधिकार अवकाश के नकदीकरण के लिए पात्र होगा।"

- (ख) उप-विनियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"(5) विशेषाधिकार अवकाश का लाभ उठाने वाले इच्छुक अधिकारी को सामान्यतः अवकाश किराया रियायत के प्रयोजन को छोड़कर, ऐसे अवकाश का लाभ उठाने के अपने इरादे की कम से कम दस दिन पहले सूचना देनी होगी।

- (ग) उप-विनियम (5) के पश्चात् निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"(6) अस्वस्थता के कारण लिए गए विशेषाधिकार अवकाश को, जब अधिकारी के पास अस्वस्थता पर अवकाश शेष न हो, विशेषाधिकार अवकाश लेने के रूप में नहीं गिना जाएगा।"

12. उक्त विनियमों के विनियम 34 में, उप-विनियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:

"(5) महिला अधिकारी अपने आठ वर्ष या उससे कम आयु के बच्चों की अस्वस्थता के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर अस्वस्थता अवकाश का लाभ उठा सकती हैं।"

12. उक्त विनियमों के विनियम 35 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:

“35 (1) अतिरिक्त अस्वस्थता पर अवकाश:— 1 जनवरी, 1989 को एवं से, जहां किसी अधिकारी का सेवाकाल चौबीस वर्ष हो गया है, वह चौबीस वर्ष से अधिक की सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए एक माह की दर से अतिरिक्त अस्वस्थता अवकाश के लिए पात्र होगा, जो अधिकतम तीन माह के अतिरिक्त अस्वस्थता अवकाश के अधीन होगा।

(2) 1 नवंबर, 2017 को एवं से, जहां किसी अधिकारी का सेवाकाल तीस वर्ष हो गया है, वह तीस वर्ष से अधिक की सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए एक माह की दर से अतिरिक्त अस्वस्थता अवकाश के लिए पात्र होगा, जो अधिकतम तीन माह के अतिरिक्त अस्वस्थता अवकाश के अधीन होगा:

बशर्ते कि अधिकारी की संपूर्ण सेवा में अस्वस्थता अवकाश की कुल संख्या सात सौ बीस दिन से अधिक नहीं होगी।

बशर्ते कि 29 जून, 1999 को या उसके पश्चात् ली गई अतिरिक्त अस्वस्थता अवकाश के मामले में, विनियम 34 के उप-विनियम (2) के अनुसार अतिरिक्त अवकाश का संराशीकरण की अनुमति दी जा सकती है।

15. उक्त विनियमों के विनियम 36 के स्थान पर निम्नलिखित विनियमन प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“36 मातृत्व अवकाश:-(1) मातृत्व अवकाश के मामले में,-

(क) कोई महिला कार्मिक किसी एक अवसर पर अधिकतम छह माह की अवधि के लिए तथा अपनी सम्पूर्ण सेवा अवधि के दौरान अधिकतम बारह माह के लिए मूल वेतन पर मातृत्व अवकाश के लिए पात्र होगी।

बशर्ते कि जुड़वा बच्चों के जन्म के मामले में मातृत्व अवकाश की अवधि आठ माह होगी:

इसके अलावा मातृत्व अवकाश के साथ आकस्मिक अवकाश को छोड़कर किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश को जोड़ा जा सकेगा;

(ख) गर्भपात होने, गर्भावस्था की चिकित्सीय समाप्ति या गर्भपात कराने के मामले में, महिला कार्मिक सक्षम चिकित्सक अर्थात् अर्हता प्राप्त स्त्री रोग विशेषज्ञ के चिकित्सा प्रमाण पत्र या परामर्श के आधार पर छह सप्ताह तक का मातृत्व अवकाश ले सकती है। गर्भपात होने, गर्भावस्था की चिकित्सीय समाप्ति या गर्भपात कराने से जुड़ी चिकित्सा जटिलताओं से जुड़े विशेष या असाधारण मामलों में, सक्षम चिकित्सक (अर्हता प्राप्त स्त्री रोग विशेषज्ञ) की सलाह पर छह सप्ताह से अधिक मातृत्व अवकाश लिया जा सकता है, लेकिन सेवा की पूरी अवधि के दौरान बारह महीने की कुल सीमा के भीतर केवल एक अवसर पर छह महीने तक का मातृत्व अवकाश लिया जा सकता है;

(ग) बारह महीने की समग्र अवधि के भीतर, गर्भाशय उच्छेदन के मामले में अधिकतम साठ दिनों तक का भी अवकाश लिया जा सकता है;

**टिप्पणी :** उन कार्मिकों के मामले में जिनके बारह महीने का मातृत्व अवकाश समाप्त हो गया है, इस अवकाश के अतिरिक्त पंद्रह दिनों का अवकाश चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अधीन, स्वीकृत किया जाएगा;

(घ) एक निःसंतान महिला कार्मिक एक वर्ष से कम आयु के बच्चे को कानूनी रूप से गोद लेने के लिए सेवा के दौरान एक बार अधिकतम नौ महीने की अवधि के लिए अवकाश ले सकती है, जो निम्नलिखित शर्तों एवं निबंधनों के अधीन है, अर्थात्: -

(i) केवल एक बच्चे को गोद लेने के लिए अवकाश दिया जाएगा;

(ii) बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया उचित कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से होनी चाहिए तथा ऐसी अवकाश स्वीकृति के लिए कार्मिक को बैंक के समक्ष गोद लेने का दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहिए;

- (iii) स्थायी अंशकालिक कार्मिक भी बच्चे को गोद लेने के लिए अवकाश प्राप्त करने के लिए पात्र हैं;
  - (iv) यह अवकाश उन मामलों में बायोलोजिकल मां को भी उपलब्ध होगा जहां बच्चा सरोगेसी के माध्यम से पैदा हुआ हो;
  - (v) अवकाश का लाभ सम्पूर्ण सेवा अवधि के दौरान बारह महीने की समग्र पात्रता के भीतर लिया जाएगा;
  - (ड) बारह महीने की समग्र अवधि के भीतर, निम्नलिखित स्त्री रोग संबंधी बीमारियों या उपचारों के कारण अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में भी अधिकतम तीस दिनों तक अवकाश का लाभ लिया जा सकता है, अर्थात्: -
    - i. एयूबी (असामान्य गर्भाशय रक्तस्राव);
    - ii. ओवेरियन ट्यूमर;
    - iii. ट्यूबेक्टोमी/ट्यूबेक्टोमी रिवर्सल;
    - iv. प्रसवोत्तर अवसाद (पीपीडी);
    - v. प्रसवोत्तर रक्तस्राव (पीपीएच);
    - vi. अक्यूट पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज (तीव्र पीआईडी )
    - vii. डिसफंक्शन गर्भाशय रक्तस्राव; डिसफंक्शन (डीयूबी)।
  - 2. पितृत्व अवकाश के मामले में, 1 जून 2015 से , दो जीवित बच्चों तक वाले पुरुष कार्मिक अपनी पत्नी के प्रसव के दौरान पंद्रह दिनों के पितृत्व अवकाश के लिए पात्र होंगे तथा यह अवकाश आकस्मिक अवकाश को छोड़कर किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है:
- बशर्ते कि अवकाश बच्चे के जन्म की तिथि से पंद्रह दिन पहले या छह महीने तक अवकाश का लाभ उठाया जा सकता है :
- उपर्युक्तानुसार पितृत्व अवकाश दो जीवित बच्चों वाले पुरुष कार्मिक को एक वर्ष से कम आयु के बच्चे को कानूनी रूप से गोद लेने के लिए दिया जाएगा ।"

16. उक्त विनियमों के विनियम 37 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

- "37. असाधारण अवकाश- (1) कोई अधिकारी संपूर्ण सेवा अवधि के दौरान अधिकतम चौबीस माह के लिए वेतन हानि सहित असाधारण अवकाश के लिए पात्र होगा।
- (2) कोई भी अधिकारी किसी एक अवसर पर तीन माह से अधिक अवधि के लिए असाधारण अवकाश का लाभ उठा सकता है तथा अत्यंत चिकित्सीय परिस्थितियों में वह किसी एक अवसर पर चार माह तक का असाधारण अवकाश ले सकता है।

**नोट –** चिकित्सा आधार पर असाधारण अवकाश लेने के कारण कार्मिक की वरिष्ठता में कोई हानि नहीं होगी।

17. उक्त विनियमों के विनियम 37ए के स्थान पर निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किए जाएं, अर्थात्:-

37ए विशेष आकस्मिक अवकाश तथा विशेष अवकाश - (1) 1 नवंबर, 2020 से, कोई अधिकारी कार्मिक ऐसे अवसरों पर विशेष आकस्मिक अवकाश के लिए पात्र होगा, जब ऐसी शाखा जहां अधिकारी कार्यरत है या वह स्थान जहां वह निवास कर रहा है, कर्फ्यू, दंगे, निषेधाज्ञा, प्राकृतिक आपदा, बाढ़ आदि से प्रभावित हो।

(2) 1 नवंबर, 2020 से कोई शारीरिक या अस्थि विकलांग अधिकारी चार दिन के विशेष आकस्मिक अवकाश के लिए पात्र होगा।

(3) किसी अधिकारी को विशेष आकस्मिक अवकाश या कोई भी विशेष अवकाश प्रदान किया जा सकता है, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार बोर्ड द्वारा तय किया जाएगा।”

18. उक्त विनियम के विनियम 41 में, उप-विनियम (4) में, खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“(क) विराम भत्ता.- 1 नवंबर 2020 को एवं से , तालिका के कॉलम (1) में दिए गए ग्रेड या स्केल में कोई अधिकारी कॉलम (2) में दी गई तत्संबंधी दरों पर 'दैनिक' विराम भत्ते का हकदार होगा, अर्थात्:

तालिका

क्र. सं.	अधिकारियों के ग्रेड/स्केल	महानगर रु.	प्रमुख 'ए' श्रेणी के शहर रु.	क्षेत्र - I रु.	अन्य स्थान रु.
1.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	स्केल VI तथा उससे ऊपर के अधिकारी	2700	1950	1650	1425
3.	स्केल IV तथा V के अधिकारी	2250	1950	1650	1425
4.	स्केल I, II तथा III के अधिकारी	1950	1650	1425	1200

बशर्ते कि जहां अनुपस्थिति की कुल अवधि आठ घंटे से कम किन्तु चार घंटे से अधिक हो, वहां उपर्युक्त दरों की आधी दर पर विराम/स्थिर भत्ता देय होगा।

**स्पष्टीकरण-** विराम भत्ते की गणना करने के प्रयोजन के लिए "दैनिक" का अर्थ चौबीस घंटे की प्रत्येक अवधि या उसका कोई पश्चातवर्ती भाग होगा, जिसकी गणना हवाई यात्रा के मामले में प्रस्थान के लिए रिपोर्टिंग समय से या अन्य मामलों में प्रस्थान के निर्धारित समय से लेकर आगमन के वास्तविक समय तक की जाएगी तथा जहां अनुपस्थिति की कुल अवधि चौबीस घंटे से कम है, वहां "दैनिक" का अर्थ आठ घंटे से कम की अवधि नहीं होगी।”

19. उक्त विनियमों के विनियम 42 में, उप-विनियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

(3) 1 नवम्बर, 2020 को एवं से, स्थानांतरण पर आने वाला अधिकारी पैकिंग, स्थानीय परिवहन, सामान का बीमा आदि से जुड़े खर्चों के लिए एकमुश्त राशि प्राप्त करने के लिए पात्र होगा, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में निर्दिष्ट है, अर्थात्: -

"तालिका

क्रम सं.	ग्रेड या स्केल	मात्रा
1.	(1)	(2)
2.	शीर्ष कार्यपालक तथा वरिष्ठ प्रबंधन (स्केल IV तथा उससे ऊपर के अधिकारी)	रु.30,000/-
3.	मध्यम प्रबंधन तथा कनिष्ठ प्रबंधन ( स्केल III तक के अधिकारी )	रु. 25,000/-.”

20. उक्त विनियमों के विनियम 45 में, उप-विनियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित प्रावधान अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्: -

“ बशर्ते कि परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना (नई पेंशन योजना) के अंतर्गत आने वाले अधिकारियों के संबंध में, बैंक 11 नवंबर, 2020 से वेतन तथा महंगाई भत्ते का चौदह प्रतिशत का अंशदान करेगा:

बशर्ते कि बैंक द्वारा नई पेंशन योजना के सेवा प्रदाता या निधि प्रबंधक के सेवा प्रभारों को वित्तीय वर्ष 2020-21 से वहन किया जायेगा।”

21. उक्त विनियमों की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्: -

**"अनुसूची**

**[ विनियम 23 का उप-विनियम (2) देखें ]**

1 नवंबर, 2017 से कोई भी अधिकारी विशेष क्षेत्र भत्ते के लिए तब तक पात्र होंगे जब तक कि उसे नीचे दी गई तालिका में निर्दिष्ट अनुसार पूरी तरह या आंशिक रूप से हटाया नहीं जाता या संशोधित नहीं कर दिया जाता है, अर्थात्: -

**तालिका**

**विशेष क्षेत्र भत्ता**

क्र. सं.	क्षेत्र	भत्ते (रु.)	
		वेतन रु.36,001/- से कम	रु. 36,001/- से अधिक वेतन
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	<b>मिजोरम</b> (क) चिम्पटुइपुई जिला तथा 25 किलोमीटर से आगे के क्षेत्र लुंगलेई जिले के लुंगलेई कस्बे से।  (ख) लुंगलेई शहर से 25 किलोमीटर से बाहर के क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण लुंगलेई जिला। (ग) संपूर्ण आइजोल जिला	4000  3200 2400	5200  4200 3000
2.	<b>नागालैंड</b>	3200	4200
3.	<b>अंडमान व निकोबार द्वीप समूह</b> (क) उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, छोटा अंडमान, निकोबार तथा नारकोंडम द्वीप समूह (ख) दक्षिण अंडमान (पोर्ट ब्लेयर सहित)	4000  3200	5200  4200
4.	<b>सिक्किम</b>	4000	5200
5.	<b>लक्षद्वीप द्वीप समूह</b>	4000	5200
6.	<b>असम</b>	640	800
7.	<b>मेघालय</b>	640	800
8.	<b>त्रिपुरा</b>	3200	4200

क्र. सं.	क्षेत्र	भत्ते (रु.)	
		वेतन रु.36,001/- से कम	रु. 36,001/- से अधिक वेतन
(1)	(2)	(3)	(4)
	(क) त्रिपुरा के दुर्गम क्षेत्र		
	(ख) दुर्गम क्षेत्रों को छोड़कर सम्पूर्ण त्रिपुरा में।	2400	3000
9.	मणिपुर	2400	3000
10.	अरुणाचल प्रदेश		
	(क) अरुणाचल प्रदेश के दुर्गम क्षेत्र	4000	5200
	(ख) संपूर्ण अरुणाचल प्रदेश में, दुर्गम क्षेत्रों को छोड़कर।	3200	4200
11.	जम्मू तथा कश्मीर		
	(क) कठुआ जिला: नियाबतबानी , लोही , मल्हार तथा मल्लोडी	4000	5200
	(ख) उधमपुर जिला: (i) दुदु बसंतगढ़ , लैंडर भमागइलका , भाग 2(बी) में शामिल लोगों के अलावा। (ii) तहसील मोहरे में कंबन की ओर से गोयल तक का क्षेत्र तथा केसी की ओर से अरनास तक का क्षेत्र।	4000 3200	5200 4200
	(ग) डोडा जिला: किश्तवाड़ तहसील में पैडर तथा नियाबतनौगाम के इलाक़ास	4000	5200
	(घ) लेह जिला : जिले के सभी स्थान	4000	5200
	(ङ) बारमुल्ला जिला: (i) संपूर्ण गुरेज़- निराबत, टंगडार सब-डिवीजन तथा केरानइलाक़ा (ii) मैचिल	4000 3200	5200 4200
	(च) पुंछ तथा राजौरी जिले: पुंछ तथा राजौरी जिले के क्षेत्र (पुंछ तथा राजौरी कस्बों तथा सुंदरबनी तथा दोनों जिलों के अन्य शहरी क्षेत्रों को छोड़कर)	2400	3000
	(छ) वे क्षेत्र जो उपरोक्त (1) से (6) में सम्मिलित नहीं हैं, किन्तु जो वास्तविक नियंत्रण रेखा से 8 कि.मी. की दूरी के भीतर हैं या ऐसे स्थान हैं जिन्हें राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अपने कार्मिकों के लिए सीमा भत्ते के लिए अर्हक घोषित किया जा सकता है।	2400	3000



क्र. सं.	क्षेत्र	भत्ते (रु.)	
		वेतन रु.36,001/- से कम	रु. 36,001/- से अधिक वेतन
(1)	(2)	(3)	(4)
12.	हिमाचल प्रदेश		
	(1) चम्बा जिला		
	(क) पांगी तहसील, भरमौर तहसील, पंचायतें: बडगांव , बजोल , देवलकुगती , नयागाम तथा तुंदाह , गांव: ग्राम पंचायत जगत के घाटू , ग्राम पंचायत चौहाटा के कनारसी	4000	5200
		3200	4200
	(ख) भरमौर तहसील, उपरोक्त (क) में शामिल पंचायतों तथा गांवों को छोड़कर।	2400	3000
	(ग) भटिया तहसील में झंडरू पंचायत , चुराह तहसील, डलहौजी टाउन ( बनीखेत सहित )।		
	(2) किन्नौर जिला:		
	(i) असरंग, छितकुल तथा हांगोकुनो / चारंग पंचायतें, 15/20 छोटाखंबा, नाथपा तथा रूपी, पूह उप-मंडल की ग्राम पंचायतों को शामिल करने वाला क्षेत्र, ऊपर निर्दिष्ट पंचायत क्षेत्रों को छोड़कर।	4000	5200
		3200	4200
	(ii) उपरोक्त (क) में शामिल क्षेत्रों के अलावा संपूर्ण जिला।		
	(3) कुल्लू जिला:		
	(i) निरमंड तहसील का 15/20 क्षेत्र , जिसमें खरगा , कुशवार तथा सरगा ग्राम पंचायतें शामिल हैं	4000	5200
	(ii) [बाहरी सराज (निरमंड तहसील के जकात-खाना तथा बरो के गांवों को छोड़कर) तथा संपूर्ण जिला, बाहरी सराज क्षेत्र तथा पंद्राबीस के परगना को छोड़कर, लेकिन तहसील निरमंड के जगत-खाना तथा बरो के गांवों को शामिल करते हुए ]	2400	3000
	(4) लाहौल तथा स्पीति जिला:		
	लाहौल तथा स्पीति का संपूर्ण क्षेत्र	4000	5200
	(5) शिमला जिला:		
	(i) रामपुर तहसील का 15/20 क्षेत्र जिसमें कूट, लबाना-सदाना, सरपारा तथा चाडी-ब्रांडा की पंचायतें शामिल हैं।	3200	4200

क्र. सं.	क्षेत्र	भत्ते (रु.)	
		वेतन रु.36,001/- से कम	रु. 36,001/- से अधिक वेतन
(1)	(2)	(3)	(4)
	<p>(ii) डोरा-कावर तहसील, रामपुर में दरकाली की ग्राम पंचायत, काशापथ तहसील तथा परगना सराहन के मुनीश, गोरीचैबीस ।</p> <p>(iii) चौपाल तहसील तथा परगना सराहन के घोरी , पंजगांव , पाटसनौ , नौबीस तथा तीन कोटी , तकलेश क्षेत्र की देवठी ग्राम पंचायत , परगना बाराबीस , रामपुर तहसील के परगना रामपुर के कस्बा रामपुर तथा गौरी नोग , शिमला शहर तथा इसके उपनगर ( ढल्ली , जटोग, कसुम्पटी , मशोबरा ) , तारादेवी तथा टूट)।</p>	2400	3000
	<p>(6) कांगड़ा जिला:</p> <p>(i) बड़ा भंगाल तथा छोटा भंगाल के क्षेत्र</p> <p>(ii) कांगड़ा जिले का धर्मशाला शहर तथा नगरपालिका सीमा के बाहर स्थित लेकिन धर्मशाला शहर में शामिल निम्नलिखित कार्यालय-महिला आईटीआई, दाड़ी, यांत्रिक कार्यशाला, रामनगर , बाल कल्याण तथा नगर एवं ग्राम नियोजन कार्यालय, सकोह , निचले सकोह में सीआरएसएफ कार्यालय, कांगड़ा दूध आपूर्ति योजना, डुगियार , एचआरसी वर्कशॉप, सधेर , क्षेत्रीय मलेरिया कार्यालय, दाड़ी, वन निगम कार्यालय, शामनगर , चाय फैक्टरी, दाड़ी, आईपीएच उप-मंडल, दान, बंदोबस्त कार्यालय, शामनगर , हिंवा परियोजना, शामनगर ।</p> <p>कांगड़ा जिले का पालमपुर शहर जिसमें पालमपुर में एचपीकेवीवी परिसर तथा इसके नगरपालिका सीमाओं के बाहर स्थित निम्नलिखित कार्यालय शामिल हैं, लेकिन पालमपुर शहर में शामिल हैं - एचपी कृषि विश्वविद्यालय परिसर, मवेशी विकास कार्यालय / जर्सी फार्म, बनूरी , सेरीकल्चर कार्यालय / इंडो-जर्मन कृषि कार्यशाला / एचपीपीडब्ल्यूडी डिवीजन, बुंडला , इलेक्ट्रिकल सब-डिवीजन, लोहना , डीपीओ निगम, बुंडला , इलेक्ट्रिकल एचईएसईई डिवीजन, घुगर ।</p>	<p>3200</p> <p>2400</p>	<p>4200</p> <p>3000</p>

क्र. सं.	क्षेत्र	भत्ते (रु.)	
		वेतन रु.36,001/- से कम	रु. 36,001/- से अधिक वेतन
(1)	(2)	(3)	(4)
	<p>(7) मंडी जिला:</p> <p>जोगिंदरनगर तहसील की छुहार घाटी , थुनाग तहसील की पंचायतें- बागरा , छतरी, छोटधार , गरागुशैन , गटू, गरयास , जंजैहली , जरयार , जोहार, कल्हणी , कलवन , खोलानाल , लोथ, सिलीबागी , सोमाचन , थाचधार , ताची, थाना, पंचायतें धरमपुर ब्लॉक- बिगा, कमलाह , सकलाना , तन्यार तथा ताराखोला, करसोग तहसील की पंचायतें - बालीधार , बागरा , गोपालपुर, खजोल , महोग, मेहुड़ी , मंज , पेखी , सैंज , सराहन तथा तेबन, सुंदरनगर तहसील की पंचायतें - बोही, बटवाडा , धन्यारा , पौरा-कोठी, सेरी तथा शोजा।</p>	2400	3000
	<p>(8) सिरमौर जिला:</p> <p>बाखली (पच्छाद तहसील), भरोगभनेरी (पांवटा तहसील), बिड़ला (नाहन तहसील), डिब्बर (पच्छाद तहसील) तथा थानाकसोगा (नाहन तहसील) तथा थांसगिरि क्षेत्र की पंचायतें</p>	2400	3000
	<p>(9) सोलन जिला:</p> <p>मंगल पंचायत.</p>	2400	3000
	<p>(10) हिमाचल प्रदेश के शेष क्षेत्र जो उपर्युक्त (1) से (9) में सम्मिलित नहीं हैं।</p>	640	800
13.	<p>उत्तर प्रदेश:</p> <p>चमोली, पिथौरागढ़ तथा उत्तरकाशी जिलों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र</p>	4000	5200
14.	<p>उत्तराखंड:</p> <p>चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग तथा चंपावत जिलों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र</p>	4000	5200
15.	<p>पश्चिम बंगाल</p> <p>दक्षिण 24 परगना जिला</p>	1000	1000.

क्र. सं.	क्षेत्र	भत्ते (रु.)	
		वेतन रु.36,001/- से कम	रु. 36,001/- से अधिक वेतन
(1)	(2)	(3)	(4)
	सुंदरवन क्षेत्र (डैम्पियर हॉज की रेखा के दक्षिण में), अर्थात्, भानातुश खली (रामपुरा), कुमिरमारी (बगना), झिंगखाली, सजनाखाली, गोसाबा, अमलामाथी (बिद्या), कैनिंग, कुलतली, पियाली, नलगराहा, रैदिघी, भांची, पाथरप्रतिमा, भागवतपुर, सप्तमुखी, नामखाना, सिकरपुर, काकद्वीप, सागर, मौसिनी, कालीनगर, हरोआ, हिंगलगंज, बसंती, कुएमारी, कुलटोला, घुशियोघाटा (कुल्टी)		

नोट: मूल विनियमों में संशोधन भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:—

क्र.सं.	संख्या	अधिसूचना की तिथि	आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	WIE-II-MISC-6	6.11.1987	12.12.1987
2.	शून्य	16.3.1989	15.4.1989
3.	एफ-17/2/84-आईआर	31.07.90	01.09.90
4.	WIE-II-MISC-91	29.04.91	25.05.91
5.	एफ-17/2/84-आईआर	25.02.92	21.03.92
6.	WIE-II-MISC-91	20.11.92	12.12.92
7.	शून्य	06.12.94	07.01.95
8.	WIE-II-MISC-91	09.08.96	07.09.96
9.	शून्य	05.11.96	01.02.97
10.	WIE-II-MISC-91	11.03.99	10.04.99
11.	पीएल:एमआर:पीओएल:91	27.05.99	10.07.99
12.	पीएल:एमआर:पीओएल:91	14.07.2000	19.08.2000
13.	WIE:II:MISC:91	27.08.2001	29.09.2001
14.	पीएल:एमआर:पीओएल:91	02.11.2002	28.12.2002
15.	एचआरडीडी/एमआर/पीओएल/91	09.03.2006	07.04.2006
16.	एचआरडीडी/एमआर/पीओएल/91	04.09.2006	08.09.2006
17.	एचआरडीडी/ओएसआर/पीओएल/11(2)	18.12.2017	13.01.2018
18.	एचआरडीडी/पीओएल/ओएसआर(ई)	27.03.2020	27.03.2020

सुरेश कुमार राणा, मुख्य महाप्रबंधक

[विज्ञापन-III/4/असा./725/2024-25]

### विवरणात्मक ज्ञापन

उक्त विनियम, जिन्हें पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया है, संयुक्त नोटों और निपटन के लिए सहमत शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार, संबंधित बैंकों द्वारा इस संबंध में दिए गए विशिष्ट अधिदेश के आधार पर सदस्य बैंकों की ओर से भारतीय बैंक संघ तथा बैंकों के शीर्ष स्तरीय अधिकारी संघों के बीच हस्ताक्षरित है। अतः, ऐसे पूर्वव्यापी प्रभाव से किसी भी व्यक्ति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

## PUNJAB NATIONAL BANK

### NOTIFICATION

New Delhi, the 29th October, 2024

**F. No. HRDD/POL/OSR(E).**—In exercise of the powers conferred by section 19, read with sub-section (2) of section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of the Punjab National Bank, after consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, except as respects things done or omitted to be done in pursuance of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services letter No. 4/2/2015-IR, dated the 18<sup>th</sup> December, 2020, on and from the 1<sup>st</sup> November, 2017 till the date of publication of this notification in the Official Gazette, hereby makes the following regulations further to amend the Punjab National Bank (Officers') Service Regulations, 1979, namely:-

1. (1) These regulations may be called the Punjab National Bank (Officers') Service (Amendment) Regulations, 2024.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the official gazette.
2. In the Punjab National Bank (Officers') Service Regulations, 1979 (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 3,—
  - (i) for clause (f), the following clause shall be substituted, namely: —
 

"(f) "Family" for the purposes of medical facilities and for the purpose of leave fare concession means, the spouse of the officer, wholly dependent unmarried children (including step children and legally adopted children), wholly dependent physically and mentally challenged brother or sister with forty per cent. or more disability, widowed daughters and dependent divorced or separated daughters, sisters including unmarried or divorced or abandoned or separated from husband or widowed sisters, and parents wholly dependent on the officer.

#### **Explanation.—**

- (a) The expression "wholly dependent family member" shall mean such member of the family having an income not exceeding **₹12,000/- per month**. If the income of one of the parents exceeds **₹12,000/- per month** or the aggregate income of both the parents exceeds **₹12,000/- per month**, both the parents shall not be considered as wholly dependent on the officer.
- (b) A married female officer may include her natural parents or parents-in-law under the definition of family, but not both, provided that the parents or parents-in-law are wholly dependent on her.

**Note 1:** For the purpose of medical expenses reimbursement scheme, for all officers i.e., male or female, any two of the dependent parents or parents-in-law shall be covered. The officer will have the choice to substitute either of the dependents or both.

**Note 2:** Physically challenged children of an officer to be defined as dependents irrespective of age or marital status, subject to income criteria;"

- (ii) for clause (i), the following clause shall be substituted, namely:—

"(i) 'Managing Director' means the Managing Director and the Chief Executive Officer of the Bank;"

3. In regulation 4 of the said regulations, —

- (i) in sub-regulation (6), the *Explanation* shall be omitted;

(ii) for sub-regulations (7), (8) and (9), the following sub-regulations shall be substituted, namely:—

“(7) With effect from the 1st November, 2017, the scales of pay specified against each grade shall be as under:—

(a) Top Executive Grade

Scale VII = ₹116120 – 3220/4 – 129000

Scale VI = ₹104240 – 2970/4 – 116120

(b) Senior Management Grade

Scale V = ₹ 89890 – 2500/2 – 94890 – 2730/2 – 100350

Scale IV = ₹ 76010 – 2220/4 – 84890 – 2500/2 – 89890

(c) Middle Management Grade

Scale III = ₹ 63840-1990/5– 73790 - 2220/2 - 78230

Scale II = ₹ 48170–1740/1 - 49910 -1990/10 - 69810

(d) Junior Management Grade

Scale I = ₹ 36000-1490/7- 46430-1740/2-49910-1990/7-63840.

**Explanation.**— Every officer who is governed by the scales of pay as in force as on 31<sup>st</sup> October, 2017 shall be fitted in the scale of pay set out as in this sub-regulation as on 1<sup>st</sup> November, 2017 on stage-to-stage basis, i.e., on corresponding stages from first stage onwards in the respective scales and the increments shall fall on the anniversary date as usual except where provided otherwise.

(8) With effect from the 31<sup>st</sup> March, 2020, the scales of pay specified for Top Executive Grade Scale – VIII shall be as under:—

Scale VIII = Rs 166350-4400/4 - 183950

(9) Nothing in sub-regulations (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) and (8) shall be construed as requiring the Bank to have at all times, officers serving in all these grades.

(10) (a) With effect from 1<sup>st</sup> November, 2012, officers shall be paid special allowances as under:—

Scale I – III - 7.75 % of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon;

Scale IV – V - 10% of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon;

Scale VI – VII - 11 % of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon.

(b) With effect from 1st November, 2017, officers shall be paid special allowances as under:—

Scale I – III - 16.40 % of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon;

Scale IV – V - 19 % of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon;

Scale VI - VIII - 20 % of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon.

Provided that an officer in Scale VIII will be eligible for special allowance with effect from the 31<sup>st</sup> March, 2020.

**Note:** The special allowance referred to in clauses (a) and (b) of sub-regulation 10 with applicable dearness allowance thereon shall not be reckoned for superannuation benefits, such as pension including New Pension scheme, Provident Fund and Gratuity.”.

4. In regulation 5 of the said regulations, —

(i) for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely: -

“(1) Subject to the provisions of sub-regulation (7) and (8) of regulation 4, on and from the 1<sup>st</sup> November, 2017, the increments shall be granted subject to the following, namely: -

- (a) the increments specified in the scales of pay set out in sub-regulation (7) and (8) of regulation 4 shall, subject to the sanction of the Competent Authority, accrue on an annual basis and shall be granted on the first day of the month in which these fall due;
- (b) one year after reaching maximum in their respective scales, officers in Scale I and Scale II, shall be granted further increments including stagnation increment in the next higher Scale only as specified in clause (c) below subject to their crossing the efficiency bar;
- (c) officers in junior management grade Scale I who have moved to scale of pay for Middle Management Grade Scale II in terms of clause (b) after reaching maximum of the higher Scale, shall be eligible for five stagnation increments for every two completed years of service of which the first two shall be Rs. 1990/- each and the next three of Rs 2220/- each:

Provided that the officer shall be eligible for the fifth stagnation increment two years after release of fourth stagnation increment or on the 1<sup>st</sup> November 2017, whichever is later.

- (d) officers in middle management grade Scale II who have moved to scale of pay for middle management grade Scale III in terms of clause (b), after reaching maximum of higher Scale, shall be eligible for five stagnation increments of Rs 2220/- each for every two completed years of service:

Provided that the officer shall be eligible for the fifth stagnation increment two years after release of fourth stagnation increment or on the 1<sup>st</sup> November 2017, whichever is later.

- (e) officers in substantive middle management grade Scale III i.e., those who are recruited in or promoted to middle management grade Scale III shall be eligible for six stagnation increments out of which first four stagnation increments of Rs 2220/- each will be granted for every two years of completed service after reaching the maximum and the next two stagnation increments of Rs 2500/- each shall be granted for every two years of completed service after receiving the fourth stagnation increment.

Provided that the sixth stagnation increment shall be released two years after release of fifth stagnation increment or on the 1<sup>st</sup> November, 2017, whichever is later;

- (f) officers in senior management grade Scale IV shall be eligible for two stagnation increments after reaching the maximum of scale, for every two completed years of service, of which first stagnation increment shall be of Rs 2500/- and the second stagnation increment shall be of Rs 2730/-:

Provided that the officer shall be eligible for the second stagnation increment two years after release of first stagnation increment or on the 1<sup>st</sup> November, 2017, whichever is later;

- (g) the stagnation increments received by the officers from Scale I to Scale IV during their service in the banks as on 1<sup>st</sup> November, 2017 as per periodicity herein before would be readjusted from three years periodicity to two years periodicity from the date of reaching their maximum and officer shall be notionally eligible for stagnation increments w.e.f the 1<sup>st</sup> November, 2017 as per the revised periodicity which will qualify for superannuation benefits. However, monetary benefit on account of such revised and readjusted periodicity of stagnation increments shall be payable from 1<sup>st</sup> November, 2020 or the actual date of entitlement, whichever is later;

- (h) officer in senior management grade Scale V shall be eligible for one stagnation increment of Rs 2970/- two years after reaching the maximum scale of pay or on the 1<sup>st</sup> November 2020, whichever is later.

Provided that such increments shall not be allowed to an officer who refuses promotion when offered.

**Explanation.**— Grant of such increments in the next higher scale under this sub-regulation shall not amount to promotion and the privileges, perquisites, duties and responsibilities of the officers shall continue as of their substantive posts.”;

- (ii) in sub-regulation (2), in the *Explanation*, after clause (g) and before the Note, the following clause shall be inserted, namely: -

“(h) On and from the 1<sup>st</sup> November, 2017, other things being equal, the quantum of professional qualification pay shall stand revised as specified in the table below: -

TABLE

Those who have passed Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Certified Associate of Indian Institute of Bankers Part I	(i) Rs. 1020 per month one year after reaching maximum of the Scale.
Those who have passed both parts of Certified Associate of Indian Institute of Bankers	(i) Rs. 1020 per month one year after reaching maximum of the Scale. (ii) Rs. 2550 per month two years after reaching maximum of the Scale:

Provided that an officer employee acquiring Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Certified Associate of Indian Institute of Bankers (either or both parts) qualifications after reaching the maximum of the scale of pay, shall be granted from the date of acquiring such qualification the first installment of professional qualification pay and the release of subsequent installments of professional qualification pay shall be with reference to the date of release of first installment of professional qualification pay.”;

- (iii) in sub-regulation (3), -

(a) in clause (f), after the Table, note (i) to (vi) shall be omitted;

(b) for clause (g), the following clause shall be substituted, namely:

“(g) on and from the 1<sup>st</sup> November, 2017, other things being equal, fixed personal pay together with house rent allowance shall be at the following rates and shall remain frozen for the entire period of service:

TABLE

Sl. No.	Increment component (Rs.)	Dearness Allowance as on the 1 <sup>st</sup> November, 2017 on the increment components (Rs.)	Total Fixed Personal Pay payable where bank's accommodation is provided (Rs.)
1	(1)	(2)	(3)
2	1990	53	2043
3	2220	59	2279
4	2500	66	2566
5	2730	73	2803
6	2970	79	3049
7	3220	86	3306

**Note:**

- (i) fixed personal allowance or fixed personal pay as indicated under column (3) of the Tables in clauses (b), (c), (d), (e), (f) and (g) of this sub-regulation shall be payable to those officer employees who are provided with bank's accommodation.
- (ii) fixed personal allowance or fixed personal pay for officers eligible for House Rent Allowance shall be the aggregate amount specified under columns (1) and (2) of the Table aforesaid and House Rent Allowance drawn by the concerned officer employees when the last increment of the relevant scale of pay as specified in sub-regulations (2), (3), (4), (5) (6) and (7) of regulation 4 is earned;
- (iii) Only officers who are in the service of the Bank on or before 1<sup>st</sup> November, 1993 will be eligible for Fixed Personal Pay one year after reaching the maximum scale of pay, they are placed.



- (iv) On and from 1<sup>st</sup> November, 1999, there shall be no change in the schedule of release of professional qualification pay as in explanation (c) of sub-regulation (2) on account of release of Fixed Personal Pay:

Provided that where any installment of professional qualification pay which on account of the earlier provisions has been shifted by a year and is scheduled for release on or after 1<sup>st</sup> November, 1999, it shall be released to the Officer on and from this date and second installment of professional qualification pay, if any, shall be released on 1<sup>st</sup> November, 2000.

- (v) The increment component of Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay shall rank for superannuation benefits.
- (vi) An officer who has earned the advance increment as in clause (a) above shall draw the quantum of Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay as mentioned in clauses (b), (c), (d), (e) and (f) above, one year after reaching the maximum of the scale.
- (h) On and from 31<sup>st</sup> March 2020, other things being equal, the Fixed Personal Pay together with House Rent Allowance for the post of Chief General Manager in Top Executive Grade Scale – VIII shall be at the rates given in the Table below and shall remain frozen for the entire period of service:

TABLE

Increment component (Rs.)	Dearness Allowance on the increment components (Rs.)	Total Fixed Personal Pay payable where bank's accommodation is provided (Rs.)
(1)	(2)	(3)
4400	117	4517"

5. In regulation 20 of the said Regulations, in sub-regulation (1), in clause (c), the words "Chairman and" shall be omitted.
6. In regulation 21 of the said regulations,—
- (a) in sub-regulation (6), in the *Explanation*, in clause (b), for the brackets, word and letters "(f) and (g)", the brackets, word and letters "(f), (g) and (h)", shall be substituted.
- (b) After sub-regulation (6), the following sub-regulation shall be inserted, namely: -
- "(7) On and from the 1<sup>st</sup> November, 2017, dearness allowance shall be payable for every rise or fall of four points over 6352 points in the quarterly average of the All India Average Working Class Consumer Price Index (General) Base 1960=100 at 0.07% of Pay."
7. In regulation 22 of the said regulations, for sub-regulations (1), the following sub-regulations shall be substituted, namely: -
- "(1) On and from the 1<sup>st</sup> November, 2017,—
- (a) where an officer is provided with residential accommodation by the Bank, a sum equal to 0.50 per cent of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less, shall be recovered from him;
- (b) where an officer is not provided any residential accommodation by the Bank, he shall be eligible for House Rent Allowance at the rates specified in the following table, namely:—

TABLE

Sl. No.	Place of work	House Rent Allowance
1.	(2)	(3)
2.	Major "A" Class Cities and Project Area Centres in Group A	9.0% of Pay
3.	Other places in Area I and Project Area Centres in Group B and State of Goa	8.0% of Pay
4.	Other places	7.0% of Pay:

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him shall be the actual rent paid by him for the residential accommodation in excess over 0.50 per cent of pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed with a maximum of 150 per cent of the House Rent Allowance payable as per aforesaid rates mentioned in column (2) of the above Table.

**Note:** -The claims of officers for House Rent Allowance linked to the cost of their ownership accommodation shall be also be restricted to 150 per cent of House Rent Allowance as hitherto.”.

8. In regulation 23 of the said regulations,

(A) For sub-regulations (1), (2), (3), (4) and (5), the following sub-regulations shall respectively be substituted, namely: —

“(1) On and from the 1<sup>st</sup> November, 2017, if an officer is serving in a place mentioned in Column (1) of the Table below, a city compensatory allowance at the rate mentioned in Column (2) thereof against that place shall be payable:—

**TABLE**

Sl. No.	Places	Rate
(1)	(2)	(3)
1.	Places in Area 1 and above and in the State of the Goa	Rs. 1400/- per month
2.	Places with population of five lakhs and over and state capitals and Chandigarh, Puducherry and Port Blair	Rs. 1150/- per month

- (2) On and from the 1<sup>st</sup> November, 2017, the rates of special areas allowances shall be as specified in the Schedule to these regulations.
- (3) On and from the 1<sup>st</sup> November, 2017, if an officer is serving in an area specified as Project Area falling in Group A or Group B, he shall be eligible for a Project Area Compensatory Allowance at the rate of Rs.600/- per month or Rs.525/- per month according to the classification of area as Group ‘A’ or Group ‘B’ respectively.
- (4) On and from the 1<sup>st</sup> November, 2020, if an officer is transferred from one place to another in the midst of an academic year and if he has one or more children studying in school or college, in the former place, he shall be eligible for a mid-academic year transfer allowance of Rs 1650/- per month from the date he reports to the latter place upto the end of the academic year in respect of all the children, provided that such allowance shall cease if all the children cease studying at the former place.
- (5) On and from the 1<sup>st</sup> November, 2020, if an officer is deputed to serve outside the Bank, he may opt to receive the emoluments attached to the post to which he is deputed, or he may in addition to his pay, draw a deputation allowance at the rate of 7.75 per cent. of pay subject to a maximum of Rs.6000/- per month and such other allowances he would have drawn had he been posted in the Bank’s service at that place:

Provided that where he is deputed to an organisation which is located at the same place where he was posted immediately prior to his deputation, he shall receive a deputation allowance equal to 4 per cent. of his pay subject to a maximum of Rs 3000/- per month:

Provided further that an officer on deputation to the training establishment of the Bank as a faculty member shall be eligible for deputation allowance at the rate of 4 per cent. of his pay subject to a maximum of Rs.3000 per month.”;

(B) for sub-regulation (8), the following sub-regulation shall be substituted, namely: -

“(8) On and from the 1<sup>st</sup> November, 2017, if the working hours during a day are split with minimum interval of two hours, an officer shall be eligible for a Split Duty Allowance at the rate of Rs.300 per month.”;

- (C) for sub-regulation (10), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

“(10) On and from 1<sup>st</sup> November 2017, an officer shall be eligible for the hill and fuel allowance as specified in the table below, namely:—

**TABLE**

Sl. No.	Place	Rate
(1)	(2)	(3)
1.	Place with an altitude of 1000 metres and above but less than 1500 metres and Mercara Town	2% of pay subject to a maximum of Rs.1125/- per month
2.	Place with an altitude of 1500 metres and above but less than 3000 metres	2.5% of pay subject to a maximum of Rs.1500/- per month
3.	Place with an altitude of 3000 metres and above	5% of pay subject to a maximum of Rs.3000/- per month”;

- (D). for sub-regulation (11), the following sub-regulations shall be substituted, namely:

“(11) On and from 1<sup>st</sup> November, 2017, an officer shall be eligible for learning allowance of Rs 600/- per month along with Dearness Allowance thereon.

- (E). after sub-regulation (11), the following sub-regulation shall be inserted, namely:

“(12) On and from 1<sup>st</sup> November 2017 an officer shall be eligible for a fixed allowance of Rs.700/- p.m. who are posted in areas other than the areas that are eligible for City Compensatory Allowance. This fixed allowance shall not be reckoned for payment of Dearness Allowance, superannuation benefits, viz, pension including New Pension Scheme, Provident Fund and Gratuity”.

“(13) From the financial year 2020-21, Performance Linked Incentive shall be payable to all officers annually based on Operating Profit or Net Profit over and above the normal salary payable. The Performance Linked Incentive (PLI) matrix mentioned below shall decide the amount payable (in number of days of pay = Basic + Dearness Allowance) depending on the annual performance of the Bank:

Sl. No.	Year-over-Year growth in operating profit	Number of days for which Salary (Basic + Dearness Allowance) shall be paid
(1)	(2)	(3)
1.	< 5%	Nil
2.	5% to 10%	5 days
3.	> 10% to 15%	10 days*
4.	> 15%	15 days*
*3 <sup>rd</sup> and 4 <sup>th</sup> slabs are payable only if the Bank has Net Profit. If a Bank has growth in Operating Profit of 5 per cent and more, but there is no Net Profit, then minimum 2 <sup>nd</sup> slab of 5 days shall be payable.”		

9. In regulation 24 of the said regulations, for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely: -

“(1) On and from the 1<sup>st</sup> November 2017, an officer shall be eligible for reimbursement of medical expenses for self and family on the strength of the officer’s own certificate of having incurred such expenditure supported by a statement of accounts for the amounts claimed as specified in the table below, namely: -

TABLE

Sl. No.	Grade	Maximum limit of reimbursement
(1)	(2)	(3)
1.	Junior Management and Middle Management Grade	Rs.10300/- per annum or the amount incurred whichever is less
2.	Senior Management and Top Executive Grade	Rs.12300/- per annum or the amount incurred whichever is less

**Note.** - (i) an officer may be allowed to accumulate unavailed medical aid so as not to exceed at any time three times the maximum amount provided above; or

(ii) for the year 2017, the reimbursement of medical expenses under the medical aid scheme shall be enhanced proportionately for two months, that is, November, 2017 and December, 2017.”.

10. In regulation 25 of the said regulations, for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely: -

“(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), it shall be open to the Bank to provide residential accommodation to an officer on payment by the officer, on and from the 1st November, 2017, a sum equal to 0.50 per cent. of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less:

Provided that where the officer is provided with furniture at such residence, a further sum equal to 0.10 per cent. of basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed shall be recovered by the Bank from him;

Provided further that, where such residential accommodation is provided by the bank, the charges for electricity, water, gas and conservancy shall be borne by the officer.”.

11. In regulation 32 of the said regulations, in sub-regulation (2), after the proviso, the following *Explanation* shall be inserted, namely:—

**“Explanation.**— For the purpose of this regulation, it is clarified that —

- casual leave not availed in the year 2017 or any subsequent years shall lapse in the following five year;
- on and from 1<sup>st</sup> November 2020, the unavailed casual leave by the officer shall be permitted on medical grounds and no medical certificate is required for the period of such un availed casual leave at a stretch not exceeding four days.”.

12. In regulation 33 of the said regulations,—

- (a) for sub-regulation (4), the following sub-regulation shall be substituted, namely: -

“(4) On and from 1<sup>st</sup> June, 2015, privilege leave may be accumulated upto not more than two hundred and seventy days except where leave has been applied and it has been refused:

Provided that encashment of privilege leave shall be restricted upto a maximum of two hundred forty days.

Provided further that from the calendar year, 2020, an officer shall also be eligible for encashment of privilege leave at the rate of five days for each calendar year at the time of any festival of his choice and an officer who have already completed fifty-five years of age as on 1<sup>st</sup> January, 2020 and above shall be eligible to encash privilege leave at the rate of seven days for each calendar year till his retirement as a one-time measure.”.

- (b) for sub-regulation (5), the following sub-regulation shall be substituted, namely:

“(5) An officer desiring to avail of privilege leave shall ordinarily give not less than ten days notice of his intention of avail of such leave except for the purpose of leave fare concession.

- (c) after sub-regulation (5), the following sub-regulation shall be inserted, namely:

“(6) Privilege leave taken on sick grounds, when there is no credit in the sick leave account of the Officer, shall not be counted as an occasion of availing privilege leave.”

13. In regulation 34 of the said regulations, after sub-regulation (4), the following sub-regulations shall be inserted, namely:

“(5) Women officers may avail sick leave for the sickness of their children of eight years and below subject to production of medical certificate.”

14. For regulation 35 of the said regulations, the following regulations shall be substituted, namely:

“35 (1) Additional sick leave:— On and from 1<sup>st</sup> January, 1989, where an officer has put in a service of twenty-four years, he shall be eligible to additional sick leave at the rate of one month for each year of service in excess of twenty-four years subject to a maximum of three months of additional sick leave.

(2) On and from 1<sup>st</sup> November, 2017, where an officer has put in thirty years of service, he shall be eligible for further additional sick leave at the rate of one month for each year of service in excess of thirty years subject to a maximum of three months of additional sick leave:

Provided that the total number of sick leave shall not exceed seven hundred and twenty days in the entire service of the officer.

Provided further that in case of additional sick leaves availed on or after 29<sup>th</sup> June 1999, commutation of additional leave may be allowed in accordance with sub-regulation (2) of regulation 34.”

15. For regulation 36 of the said regulations, the following regulation shall be substituted, namely:—

“36 Maternity leave. —(1) In case of maternity leave,—

(a) a female employee shall be eligible for maternity leave on substantive pay for a period not exceeding six months on any one occasion and twelve months during the entire period of her service.

Provided that in case of delivery of twins, the period of maternity leave shall be eight months:

Provided further that maternity leave may be availed combining with any other kind of leave except casual leave;

(b) in case of miscarriage, medical termination of pregnancy or abortion, female employee may avail maternity leave upto six weeks on the basis of medical certificate or advice of a competent medical practitioner, i.e., a qualified gynecologist. In special or exceptional cases involving medical complications, associated with miscarriage or medical termination of pregnancy or abortion, maternity leave may be availed beyond six weeks if advised by a competent medical practitioner (qualified gynecologist) but upto six months only on any one occasion, within the overall limit of twelve months during the entire period of service;

(c) within the overall period of twelve months, leave may also be availed in case of hysterectomy upto a maximum of sixty days;

**Note:** In the case of employees who have availed and exhausted maternity leave of twelve months, leave of fifteen days shall be sanctioned over and above the same, subject to production of medical certificate;

(d) a childless female employee may avail leave may once during service for legally adopting a child who is below one year of age, for a maximum period of nine months, subject to the following terms and conditions, namely: -

(i) leave will be granted for adoption of only one child;

(ii) the adoption of a child should be through a proper legal process and the employee should produce the adoption-deed to the Bank for sanctioning such leave;

(iii) the permanent part-time employees are also eligible for grant of leave for adoption of a child;

(iv) the leave shall also be available to biological mother in cases where the child is born through surrogacy;

(v) the leave shall be availed within overall entitlement of twelve months during the entire period of service;

(e) within the overall period of twelve months, leave may also be availed in case of hospitalization on account of the following gynecological ailments or treatments upto a maximum of thirty days, namely:-

- i. AUB (Abnormal uterine bleeding);
- ii. Ovarian Tumor;
- iii. Tubectomy/Tubectomy reversal;
- iv. Post-Partum Depression (PPD);
- v. Post-Partum Hemorrhage (PPH);
- vi. Acute Pelvic Inflammatory Disease (Acute PID);
- vii. Dysfunction Uterine Bleeding; Dysfunction (DUB).

2. In case of paternity leave, with effect from the 1<sup>st</sup> June 2015, male employees with upto two surviving children shall be eligible for fifteen days paternity leave during his wife's confinement and this leave may be combined with any other kind of leave except casual leave:

Provided that the leave may be availed upto fifteen days before or upto six months from the date of delivery of the child:

Provided further that paternity leave as above shall be allowed to a male employee with upto two surviving children for legally adopting a child who is below one year of age.”.

16. For regulation 37 of the said regulations, the following regulation shall be substituted, namely: -

“37. Extraordinary leave- (1) An officer shall be eligible for extraordinary leave on loss of pay for not more than twenty-four months during the entire period of service.

- (2) An officer may avail extraordinary leave on any one occasion for a period not exceeding three months and in extreme medical circumstances, he may avail extraordinary leave upto four months on any one occasion.

**Note** – The employee will not be losing any seniority on account of availing extraordinary leave on medical grounds.”.

17. For regulation 37A of the said regulations, following regulations may be substituted, namely:—

“37A. Special casual leave and special leave.— (1) With effect from the 1<sup>st</sup> November, .2020, an officer employee shall be eligible for special casual leave on occasions when the branch where the officer is working or the place where he is residing is affected by curfew, riots, prohibitory orders, natural calamities, floods, etc.

(2) With effect from the 1<sup>st</sup> November, 2020, a physically or orthopedically handicapped officer shall be eligible for four days special casual leave.

(3) An officer may also be granted special casual leave and any special leave as may be decided by the Board in accordance with the guidelines issued by the Central Government from time to time.”.

18. In regulations 41 of the said regulation, in sub-regulation (4), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely: -

“(a) Halting Allowance.—On and from the 1<sup>st</sup> November 2020, an officer in the Grades or Scales set out in column (1) of the Table shall be entitled to ‘per diem’ halting allowance at the corresponding rates set out in column (2) thereof, namely: -

**TABLE**

Sl. No.	Grades/Scales of officers	Metro Rs.	Major ‘A’ Class cities Rs.	Area I Rs.	Other Places Rs.
1.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	Officers in Scale VI and above	2700	1950	1650	1425
3.	Officers in Scale IV and V	2250	1950	1650	1425
4.	Officers in Scale I, II and III	1950	1650	1425	1200

Provided that where the total period of absence is less than eight hours but more than four hours, halting allowance at half the above rates shall be payable.

**Explanation.**— For the purpose of computing halting allowance “per diem” shall mean each period of twenty-four hours or any subsequent part thereof, reckoned from the reporting time for departure in the case of air travel and the scheduled time of departure in other cases, to the actual time of arrival and where the total period of absence is less than twenty-four hours, “per diem” shall mean a period of not less than eight hours.”.

19. In regulation 42 of the said regulations, for sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be substituted, namely: -

“(3) On and from the 1<sup>st</sup> November, 2020, an officer on transfer shall be eligible to draw a lump sum amount for expenses connected with packing, local transportation, insuring the baggage, etc., as specified in the Table below, namely: -

**“TABLE**

Sl. No.	Grade or Scale	Amount
1.	(1)	(2)
2.	Top executive and senior management (officers in Scale IV and above)	Rs.30,000/-
3.	Middle management and junior management (officers upto Scale III)	Rs. 25,000/-.”.

20. In Regulation 45 of the said Regulations, after sub-regulation (4), the following provisos shall be inserted, namely: -

“Provided that with regard to officers covered under Defined Contributory Pension Scheme (New Pension Scheme), the Bank shall make a contribution of fourteen per cent of pay plus dearness allowance with effect from the 11<sup>th</sup> November, 2020:

Provided further that the service charges of the Service Provider or Fund Manager of New Pension Scheme shall be borne by the Bank from the Financial Year 2020-21.”.

21. For the Schedule to the said regulations, the following Schedule shall be substituted, namely: -

**“Schedule**

**[See sub-regulation (2) of regulation 23]**

With effect from the 1st November, 2017, an officer shall be eligible for the special area allowance till such time they are withdrawn or modified either wholly or partially, as specified in the Table below, namely: -

**TABLE**

**Special Area Allowance**

Sl. No.	AREA	Allowances (Rs.)	
		Pay below Rs.36,001/-	Pay above Rs.36,001/-
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>1.</b>	<b>Mizoram</b>		
	(a) Chimtuipui district and areas beyond 25 kilometers from Lunglei Town in Lunglei District.	4000	5200
	(b) entire Lunglei district excluding areas beyond 25 kilometers from Lunglei town.	3200	4200
	(c) entire Aizawl District	2400	3000
<b>2.</b>	<b>Nagaland</b>	3200	4200
<b>3.</b>	<b>Andaman and Nicobar Islands</b>		
	(a) North Andaman, Middle Andamans, Little Andaman, Nicobar & Narcondum Islands	4000	5200
	(b) South Andaman (including Port Blair)	3200	4200
<b>4.</b>	<b>Sikkim</b>	4000	5200
<b>5.</b>	<b>Lakshadweep Islands</b>	4000	5200
<b>6.</b>	<b>Assam</b>	640	800

Sl. No.	AREA	Allowances (Rs.)	
		Pay below Rs.36,001/-	Pay above Rs.36,001/-
(1)	(2)	(3)	(4)
7.	<b>Meghalaya</b>	640	800
8.	<b>Tripura</b>		
	(a) Difficult areas of Tripura	3200	4200
	(b) Throughout Tripura except difficult areas.	2400	3000
9.	<b>Manipur</b>	2400	3000
10.	<b>Arunachal Pradesh</b>		
	(a) Difficult areas of Arunachal Pradesh	4000	5200
	(b) Throughout Arunachal Pradesh other than difficult areas.	3200	4200
11.	<b>Jammu &amp; Kashmir</b>		
	(a) Kathua district: NiabatBani, Lohi, Malhar and Machhodi	4000	5200
	(b) Udhampur district: (iii) DuduBasantgarh, Lander BhamagIllaqa, other than those included in Part 2(b). (iv) Areas uptoGoel from Kamban Side and areas uptoArnas from Keasi side in Tehsil Mohre.	4000 3200	5200 4200
	(c) Doda district: Illaquas of Padder and NiabatNowgam in Kishtwar tehsil	4000	5200
	(d) Leh district : all places in the District	4000	5200
	(e) Barmulla district: (iii) Entire Gurez-Nirabat, Tangdar Sub-Division and KeranIllaqua (iv) Matchill	4000 3200	5200 4200
	(f) Poonch and Rajouri district: areas in Poonch and Rajouri district excluding the towns of Poonch and Rajouri and Sunderbani and other urban areas in the two Districts	2400	3000
	(g) Areas not included in (1) to (6) above, but which are within the distance of 8 kms. from the line of Actual Control or at places which may be declared as qualifying for border allowance from time-to-time by the State Government for their own staff.	2400	3000
12.	<b>Himachal Pradesh</b>		
	(1) Chamba district		
	(a) Pangi tehsil, Bharmour tehsil, Panchayats:Badgaun, Bajol, DeolKugti, Nayagam and Tundah, Villages: Ghatu of Gram Panchayat Jagat, Kanarsi of Gram Panchayat Chauhata	4000 3200	5200 4200
	(b) Bharmour tehsil, excluding Panchayats and Villages included in (a) above.	2400	3000
	(c) Jhandru Panchayat in BhatiyatTehsil,Churah tehsil, Dalhousie Town (including Banikhet proper).		
	(2) Kinnaur district:		
	(iii) Asrang, Chitkul and HangoKuno/ Charang Panchayats, 15/20 Area comprising the Gram Panchayats of ChhotaKhamba, Nathpa and Rup, Pooh sub-division, excluding the panchayat areas specified above.	4000 3200	5200 4200
	(iv) entire district other than areas included in (a) above.		
	(3) Kullu district:		
	(iii) 15/20 Area of Nirmand Tehsil, comprising the Gram Panchayats of Kharga, Kushwar and Sarga	4000	5200



Sl. No.	AREA	Allowances (Rs.)	
		Pay below Rs.36,001/-	Pay above Rs.36,001/-
(1)	(2)	(3)	(4)
	(iv) [Outer-Saraj (excluding villages of Jakat-Khana and Burrow in Nirmand Tehsil) and entire district excluding outer Seraj area and pargana of Pandrabis but including villages Jagat-Khana and Burrow of tehsil Nirmand]	2400	3000
	(4) Lahaul and Spiti district: entire area of Lahaul and Spiti	4000	5200
	(5) Shimla district:		
	(iv) 15/20 area of Rampur tehsil comprising of Panchayats of Koot, Labana-Sadana, Sarpara and Chadi-Branda.		
	(v) Dora-Kawar Tehsil, Gram Panchayat of Darkali in Rampur, Kashapath tehsil and Munish, Ghorichaibis of Pargana Sarahan.	4000 3200 2400	5200 4200 3000
	(vi) Chopal tehsil and Ghoris, Panjgaon, Patsnau, Naubis and Teen Koti of Pargana Sarahan, Deothi Gram Panchayat of Taklesh Area, Pargana Barabis, Kasba Rampur and Ghor Nog of Pargana Rampur of Rampur tehsil, Simla Town and its suburbs (Dhalli, Jatog, Kasumpti, Mashobra, Taradevi and Tutu).		
	(6) Kangra district:		
	(iii) Areas of Bara Bhargal and Chhota Bhargal		
	(iv) Dharamshala Town of Kangra district and the following offices located outside the municipal limits but included in Dharamshala Town-women's ITI, Dari, mechanical workshop, Ramnagar, child welfare and town and Country Planning Offices, Sakoh, CRSF Office at lower Sakoh, Kangra Milk Supply Scheme, Dugiar, HRTC Workshop, Sadher, Zonal Malaria office, Dari, Forest Corporation office, Shamnagar, Tea Factory, Dari, I.P.H. sub-division, Dan, settlement office, Shamnagar, Hinwa project, Shamnagar.	3200	4200
	Palampur Town of Kangra district including HPKVV campus at Palampur and the following offices located outside its municipal limits but included in Palampur Town – H.P. Krishi Vishwavidyalaya Campus, Cattle Development Office/Jersey Farm, Banuri, Sericulture Office/Indo-German Agriculture Workshop/HPPWD Division, Bundla, Electrical Sub-Division, Lohna, D.P.O. Corporation, Bundla, Electrical HESEE Division, Ghuggar.	2400	3000
	(7) Mandi district:		
	Chhuahar Valley of Jogindernagar tehsil, Panchayats in thunag tehsil-of Bagraa, Chatri, Chhotdhar, Garagushain, Gatoo, Garyas, Janjehli, Jaryar, Johar, Kalhani, Kalwan, Kholanal, Loth, Silibagi, Somachan, Thachdhar, Tachi, Thana, Panchayats of Dharampur Block- Binga, Kamlah, Saklana, Tanyar and Tarakholah, Panchayats of Karsog Tehsil – Balidhar, Bagra, Gopalpur, Khajol, Mahog, Mehudi, Manj, Pekhi, Sainj, Sarahan and Teban, Panchayats of Sundernagar Tehsil – Bohi, Batwara, Dhanyara, Paura-Kothi, Seri and Shojia.	2400	3000

Sl. No.	AREA	Allowances (Rs.)	
		Pay below Rs.36,001/-	Pay above Rs.36,001/-
(1)	(2)	(3)	(4)
	(h) Sirmaur district:  Panchayats of Bani, Bakhali (Pachhad tehsil), BharogBheneri (Paonta tehsil), Birla (Nahan tehsil), Dibber (Pachhad tehsil) and ThanaKasoga (Nahan tehsil) and Thansgiri Tract	2400	3000
	(9) Solan district : Mangal Panchayat.	2400	3000
	(10) Remaining areas of Himachal Pradesh not included in (1) to (9) above.	640	800
13.	<b>Uttar Pradesh:</b>  Areas under Chamoli, Pithoragarh and Uttarkashi districts	4000	5200
14.	<b>Uttarakhand:</b>  Areas under Chamoli, Pithoragarh, Uttarkashi, Rudraprayag and Champavat districts	4000	5200
15.	<b>West Bengal</b> <b>South 24 Pargana District</b>  Sunderban Areas (south of Dampier Hodge's line), namely, Bhanatush Khali (Rampura), Kumirmari (Bagna), Jhingakhali, Sajnakhali, Gosaba, Amlamathi (Bidya), Canning, Kultali, Piyali, Nalgaraha, Raidighi, Bhanchi, PatharPratima, Bhagabatpur, Saptamukhi, Namkhana, Sikarpur, Kakdwip, Sagar, Mousini, Kalinagar, Haroa, Hingalganj, Basanti, kuemari, Kultola, Ghushioghata (Kulti)	1000	1000.”.

**Note:** The amendments to principal regulations were published in the Gazette of India as per details given below:—

Serial No.	Number	Date of Notification	Date when published in the Official Gazette
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	WIE-II-MISC-6	6.11.1987	12.12.1987
2.	Nil	16.3.1989	15.4.1989
3.	F-17/2/84-IR	31.07.90	01.09.90
4.	WIE-II-MISC-91	29.04.91	25.05.91
5.	F-17/2/84-IR	25.02.92	21.03.92
6.	WIE-II-MISC-91	20.11.92	12.12.92
7.	NIL	06.12.94	07.01.95
8.	WIE-II-MISC-91	09.08.96	07.09.96
9.	Nil	05.11.96	01.02.97
10.	WIE-II-MISC-91	11.03.99	10.04.99
11.	PL:MR:POL:91	27.05.99	10.07.99
12.	PL:MR:POL:91	14.07.2000	19.08.2000
13.	WIE:II:MISC:91	27.08.2001	29.09.2001
14.	PL:MR:POL:91	02.11.2002	28.12.2002
15.	HRDD/MR/POL/91	09.03.2006	07.04.2006
16.	HRDD/MR/POL/91	04.09.2006	08.09.2006
17.	HRDD/OSR/POL/11(2)	18.12.2017	13.01.2018
18.	HRDD/POL/OSR(E)	27.03.2020	27.03.2020

SURESH KUMAR RANA, Chief General Manager

[ADVT.-III/4/Exty./725/2024-25]

---

**EXPLANATORY MEMORANDUM**

The Regulations which have been given retrospective effect are as per the agreed terms and conditions of the Joint Notes signed between the Indian Banks' Association on behalf of member banks on the basis of specific mandate given by the respective banks in this regard and apex level officers' associations of the Banks. Therefore, interests of no person shall be adversely affected by such retrospective effect.